

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष : डा०मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3964-एक/2012 - विरुद्ध आदेश दिनांक
15-10-2012 - पारित द्वारा अपर कलेक्टर, राजगढ़ (ब्यावरा) -
प्रकरण क्रमांक 20 अ-19/2011-12

- 1- श्रीमती धापोवाई पत्नि दौलजी
 - 2- श्रीमती शैतानवाई पत्नि पर्वतसिंह
 - 3- श्रीमती कोशल्या वाई पत्नि श्रीलाल
- तीनों निवासी ग्राम मनोहरपुरा तहसील
व जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश

---आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- मध्य प्रदेश शासन
- 2- श्रीमती लक्ष्मीवाई पत्नि स्व. दिलीपकुमार
- 3- गोपाल पिता दिलीपकुमार सभी निवासी
इंगले कालोनी, तहसील व जिला राजगढ़

-- अनावेदकगण

(श्री एस०के०श्रीवास्तव अभिभाषक - आवेदकगण)
(श्री जितेन्द्र त्यागी अभिभाषक - अनावेदक 2,3)
(श्री बी०एन०त्यागी अभिभाषक - आवेदक क-1)

आ दे श

(दिनांक ०२ दिसम्बर, 2015)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, राजगढ़ (ब्यावरा) द्वारा प्रकरण
क्रमांक 20 अ-19/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 15.10.12
के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के
अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारोश यह है कि अनावेदक क-2 के पति दिलीप
कुमार को भूमि सर्वे क्रमांक 2/1/14 रकबा 2 हैक्टर का पट्टा वर्ष
2002 में कृषि कार्य हेतु दिया गया, इसी भूमि को श्रीमती शैतान
वाई, कोशल्या वाई, श्रीमती धापो वाई निवासी मनोहरपुरा को दिनांक
28-6-2010 को विक्रय कर दिया गया। पट्टाग्रहीता ने सक्षम
अनुमति के बिना भूमि विक्रय कर देने के फलस्वरूप अनुविभागीय

01

अधिकारी, राजगढ़ (व्यावरा) ने अपर कलेक्टर राजगढ़ को जांच प्रतिवेदन दिनांक 27-1-12 प्रस्तुत किया, जिस पर से आवेदकगण के विरुद्ध प्रकरण क्रमांक 20 अ-19/2011-12 पंजीबद्ध किया तथा आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 2 व 3 को बचाव प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये। पेशी 15.10.12 को आवेदकगण के अभिभाषक अपर कलेक्टर राजगढ़ के समक्ष उपस्थित हुये किन्तु चुनाव कार्य में व्यस्त रहने से आगामी पेशी 30.10.12 नियत की गई। इसी अंतरिम आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत करते हुये बताया कि आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं पक्ष समर्थन का मौके दिये बिना कार्यवाही प्रारंभ की गई जिसमें दिनांक 22.2.12, 15.3.12, 22.3.12, 19.4.12, 5.5.12, 17.5.12, 6.7.12, 17.7.12, 29.7.12, 21.8.12, 4.9.12, 9.9.12, 27.9.12 एवं 15.10.12 की पेशियाँ लगाई, किन्तु आवेदकगण को कारण बताओ सूचना पत्र आधार सहित प्रदाय नहीं किये गये। इस प्रकार अपर कलेक्टर ने क्षेत्राधिकार के वाहर जाकर मानमानी कार्यवाही की है। अनावेदक क्र. 2 व 3 के अभिभाषक ने आवेदकगण के अभिभाषक के तर्कों का समर्थन किया, किन्तु अनावेदक क्रमांक 1 के अभिभाषक ने अपर कलेक्टर द्वारा की जा रही कार्यवाही को अधिकारिता में होना बताया।

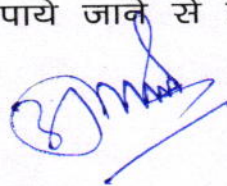
5/ उभय पक्ष की बहस पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि अनावेदक क्र-2 के पति दिलीप कुमार को भूमि सर्वे क्रमांक 2/1/14 रकबा 2 हैक्टर का पट्टा वर्ष 2002 में कृषि कार्य हेतु दिया गया था, जिसे बिना सक्षम अनुमति के श्रीमती सैतान वाई, कोशल्या वाई, श्रीमती धापू वाई निवासी मनोहरपुर को दिनांक 28-6-2010 को विक्रय किया

(5)

गया है। जैसाकि आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र आधार सहित प्रदाय नहीं किये गये, जबकि अपर कलेक्टर के प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की प्रतियाँ संलग्न हैं जिसमें पेशी 22.2.12 नियत पक्षकारों को सूचना दी गई है और पक्षकार अपर कलेक्टर के समक्ष अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित हुये है। अतः नहीं माना जा सकता कि आवेदकगण को अपर कलेक्टर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किये हैं।

6/ अपर कलेक्टर राजगढ़ को संहिता की धारा 165 के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त न होने की आपत्ति की गई है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 में व्यवस्था दी गई है कि शासकीय पट्टेदार की भूमि के विक्रय की अनुमति कलेक्टर अथवा उनसे अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा दी जायेगी। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 17 में अपर कलेक्टर को वही शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जो कलेक्टर को प्राप्त हैं। अतएव आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा उठायी गई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। अपर कलेक्टर के प्रकरण की आर्डरशीट दिनांक 15-10-2012 के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकगण जानबूझकर प्रकरण में विलम्ब करने के लिये निगरानी प्रस्तुत कर समय व्यतीत करना चाहते हैं जबकि उन्हें अपर कलेक्टर के समक्ष उपस्थित रहकर स्वच्छ मन से अपना पक्ष समर्थन एवं बचाव प्रस्तुत करना चाहिये।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः अपर कलेक्टर, राजगढ़ (व्यावरा) द्वारा प्रकरण क्रमांक 20 अ-19/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 15.10.12 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।



(डॉ० मधु खरे)
सदस्य

राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर